Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

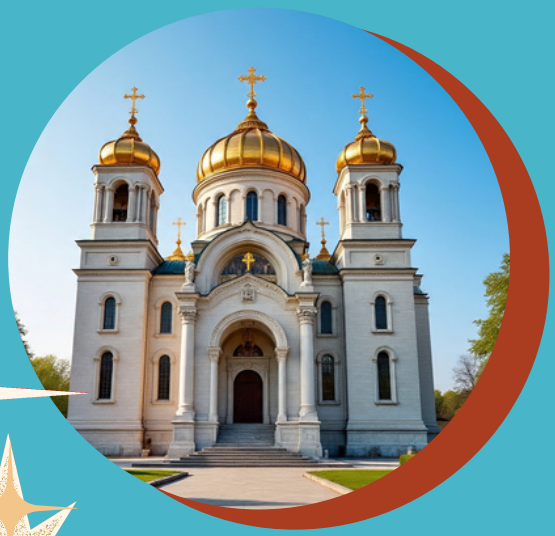

4 - 10 JAN 2026

1ST WEEK OF JANUARY

50+ MCQ with detailed explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement

Ques: How many lenders are live on RBI's Unified Lending Interface (ULI) platform as of December 12, 2025?
12 दिसंबर 2025 तक RBI के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस)ULI) प्लेटफॉर्म पर कितने ऋणदाता लाइव हैं?

A) 52
B) 58
C) 60
D) 64
E) 70

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• As of December 12, 2025, a total of 64 lenders are onboard the Reserve Bank of India's Unified Lending Interface (ULI) platform.
• 12 दिसंबर 2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस)ULI) प्लेटफॉर्म पर कुल 64 ऋणदाता शामिल हो चुके हैं।
• These include 41 banks and 23 Non-Banking Financial Companies (NBFCs).
• इनमें 41 बैंक और 23 गैर) कंपनियां वित्तीय बैंकिंग-NBFCs) शामिल हैं।
• Lenders are utilising more than 136 data services through ULI across 12 different types of loan journeys.
• ULI के माध्यम से 12 प्रकार की ऋण प्रक्रियाओं में 136 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
• The data services cover authentication and verification, land records from 8 States, satellite data, property search, dairy insights, transliteration, and credit guarantee services.
• डेटा सेवाओं में प्रमाणीकरण व सत्यापन, 8 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, संपत्ति खोज, डेयरी इनसाइट्स, ट्रांसलिटरेशन और क्रेडिट गारंटी सेवाएं शामिल हैं।
• ULI operates on a standardised, protocol-driven, open API-based plug-and-play architecture, eliminating complex one-to-one integrations between lenders and data providers.
• ULI एक मानकीकृत, प्रोटोकॉलआधारित-, ओपन API आधारित प्लगप्ले-एंड- संरचना पर कार्य करता है, जिससे ऋणदाताओं और डेटा प्रदाताओं के बीच जटिल वन की इंटीग्रेशन वन-टू- है। जाती हो समाप्त आवश्यकता
• RBI has not disclosed the total value of loans sanctioned through the ULI platform so far.

• RBI ने अब तक ULI प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वीकृत कुल ऋण राशि का खुलासा नहीं किया है।

Ques: Rediff.com India Limited has received final approval from which organisation to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP) for its digital payments platform 'RediffPay'?
रेडिफलिमि इंडिया कॉम.टेड को 'रेडिफपे' डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए थर्ड पार्टी-) प्रोवाइडर एप्लिकेशनTPAP) के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी किस संस्था से मिली है?

A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) Ministry of Electronics & IT (MeitY) / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
C) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
D) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
E) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवा विभाग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Rediff.com India Limited, a subsidiary of Infibeam Avenues Limited, received final approval from the National Payments Corporation of India (NPCI) to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP).
• इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी रेडिफ को लिमिटेड इंडिया कॉम.TPAP के रूप में कार्य करने के लिए NPCI से अंतिम मंजूरी प्राप्त हुई।
• Following the approval, the company initiated Closed User Group (CUG) testing of its digital payments platform 'RediffPay'.
• मंजूरी के बाद कंपनी ने अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म 'रेडिफपे' का क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप)CUG) परीक्षण शुरू किया।
• This testing phase is being conducted ahead of the public launch of RediffPay on the Unified Payments Interface (UPI).
• यह परीक्षण चरण UPI पर रेडिफपे के सार्वजनिक लॉन्च से पहले किया जा रहा है।

Ques: Which insurance company was penalised ₹1 crore by IRDAI for serious lapses related to claims settlement, policyholder protection, and corporate governance?
दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के लिए IRDAI ने किस बीमा कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया?

A) Star Health and Allied Insurance / स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस
B) Care Health Insurance / केयर हेल्थ इंश्योरेंस
C) HDFC ERGO Health Insurance / एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस
D) Niva Bupa Health Insurance / निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस
E) ICICI Lombard Health Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a penalty of ₹1 crore on Care Health Insurance following a remote inspection.
• बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण)IRDAI) ने रिमोट निरीक्षण के बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• The penalty was levied due to serious lapses in claims settlement, policyholder protection, and corporate governance standards.
• यह दंड दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के कारण लगाया गया।
• The charges included failure in grievance redressal, cybersecurity lapses, lack of transparency in claims settlement, reinsurance accounting irregularities, and improper handling of unidentified proposal deposits.
• आरोपों में शिकायत निवारण में विफलता, साइबर सुरक्षा में चूक, दावों के निपटान में पारदर्शिता की कमी, पुनर्बीमा लेखांकन में अनियमितताएँ तथा अज्ञात प्रस्ताव जमा राशि के अनुचित प्रबंधन शामिल थे।

Ques: As per RBI data, what was the total value of bank frauds reported in the first half of FY26 (H1FY26)?

RBI के अनुसार FY26 की पहली छमाही)H1FY26) में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि कितनी थी?

A) ₹16,569 crore
B) ₹18,336 crore
C) ₹21,515 crore
D) ₹25,000 crore
E) ₹17,501 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to RBI data, banks reported 5,092 fraud cases amounting to ₹21,515 crore during the first half of FY26 (H1FY26).
• RBI के आँकड़ों के अनुसार FY26 की पहली छमाही)H1FY26) में बैंकों ने 5,092 मामलों में ₹21,515 करोड़ की धोखाधड़ी की सूचना दी।
• The largest share of fraud value was related to advances (loans), accounting for ₹17,501 crore across 4,255 cases.
• धोखाधड़ी की सबसे बड़ी राशि ऋणरही जुड़ी से एडवांस/, जिसमें 4,255 मामलों में ₹17,501 करोड़ शामिल थे।
• Other areas of fraud included deposits, foreign exchange transactions, and card/internet-based frauds.
• धोखाधड़ी के अन्य प्रमुख क्षेत्र जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और कार्ड आधारित इंटरनेट/ रहे। धोखाधड़ी
• Compared to H1FY25, when frauds worth ₹16,569 crore were reported, the amount increased while the number of cases declined in FY26.
• H1FY25 में ₹16,569 करोड़ की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई थी, यानी FY26 में राशि बढ़ी लेकिन मामलों की संख्या घटी।
• RBI clarified that the rise in value was mainly due to reclassification and re-reporting of earlier fraud cases.
• RBI के अनुसार राशि में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पुराने मामलों का पुनर्वर्गीकरण और पुनः रिपोर्टिंग है।
• To tackle digital frauds, the AI-driven MuleHunter.ai platform has been implemented in 23 banks as of 17 December 2025 to identify mule accounts.
• डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए AI आधारित MuleHunter.ai प्लेटफॉर्म को 17 दिसंबर 2025 तक 23 बैंकों में लागू किया गया है, जो म्यूल खातों की पहचान में मदद करता है।

Ques: 'Gaj', the premium metal credit card, has been launched by which bank and is available exclusively for which category of customers?
'गज' प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है और यह विशेष रूप से किस वर्ग के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है?

A) HDFC Bank – Mass Retail Customers / एचडीएफसी बैंक – सामान्य ग्राहक
B) Axis Bank – Corporate Clients / एक्सिस बैंक – कॉरपोरेट ग्राहक
C) ICICI Bank – Premium Salary Account Holders / आईसीआईसीआई बैंक – प्रीमियम सैलरी खाताधारक
D) IDFC First Bank – High-Net-Worth Individuals (HNIs) / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक – उच्च) व्यक्ति मूल्य-निवल-HNIs)
E) SBI – Wealth Management Clients / एसबीआई – वेल्थ मैनेजमेंट ग्राहक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• 'Gaj' is a premium metal credit card launched by IDFC First Bank Limited on an invitation-only basis.
• 'गज' एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है, जिसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने केवल आमंत्रण है। किया लॉन्च पर आधार के (ओनली-इनविटेशन)
• The card is available exclusively for High-Net-Worth Individuals (HNIs).
• यह कार्ड विशेष रूप से उच्च) व्यक्तियों मूल्य-निवल-HNIs) के लिए उपलब्ध है।
• The joining fee for the 'Gaj' credit card is ₹12,500 plus applicable GST.
• 'गज' क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस ₹12,500 + लागू जीएसटी है।
• 'Gaj' represents the top tier of IDFC First Bank's premium metal credit card series known as the Ashva–Mayura–Gaj trilogy.
• 'गज' आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रीमियम मेटल कार्ड श्रृंखला 'अश्व–मयूर–गज' ट्रिलॉजी का शीर्ष स्तर है। (टियर टॉप)

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First

Ques: How much does the Government of India plan to borrow through short-term Treasury Bills (T-Bills) over 12 weeks in Q4 of the current financial year?
भारत सरकार चालू वित्त वर्ष की Q4 में 12 सप्ताह के दौरान अल्पकालिक ट्रेजरी बिल)T-Bills) के माध्यम से कितनी राशि उधार लेने की योजना बना रही है?

A) ₹2.47 lakh crore
B) ₹3.94 lakh crore
C) ₹3.50 lakh crore
D) ₹4.10 lakh crore
E) ₹3.84 lakh crore

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India plans to borrow ₹3.84 lakh crore through short-term Treasury Bills over 12 weeks in Q4 to meet short-term funding requirements.
• भारत सरकार अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए Q4 में 12 सप्ताह के दौरान ₹3.84 लाख करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी करेगी।
• Weekly T-Bill auctions will be in the range of ₹29,000 crore to ₹35,000 crore, as per the Finance Ministry.
• वित्त मंत्रालय के अनुसार साप्ताहिक T-Bill नीलामी ₹29,000 करोड़ से ₹35,000 करोड़ के बीच होगी।
• The planned Q4 borrowing is ₹10,000 crore lower than the ₹3.94 lakh crore raised in Q4 of the previous financial year.
• यह उधारी पिछले वित्त वर्ष की Q4 में जुटाए गए ₹3.94 लाख करोड़ से ₹10,000 करोड़ कम है।
• Earlier, the government had announced a Q3 T-Bill auction calendar of ₹2.47 lakh crore, ending on 31 December 2025.
• इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली Q3 T-Bill नीलामी योजना ₹2.47 लाख करोड़ की घोषित की थी।

Ques: Who published the *Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition)*, which provides a consolidated and comparable statistical

database for Indian States and Union Territories?
भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय डाटाबेस प्रदान करने वाली Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10वां संस्करण(किसके द्वारा प्रकाशित की गई है?

A) Ministry of Statistics and Programme Implementation / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
B) NITI Aayog / नीति आयोग
C) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
D) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
E) National Statistical Office / राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The *Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition)* has been published by the Reserve Bank of India (RBI).
• *Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10 वां संस्करण(* भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) द्वारा प्रकाशित की गई है।
• The handbook serves as a consolidated and comparable statistical resource for Indian States and Union Territories, with time-series data available from 1951 onwards.
• यह पुस्तिका भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय संसाधन है, जिसमें 1951 से समयहै। उपलब्ध डेटा श्रृंखला-
• It is prepared by the Regional Economy Monitoring Division (REMD) under the Department of Economic and Policy Research (DEPR), using inputs from RBI regional offices and multiple data sources.
• इसे आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग)DEPR) के अंतर्गत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था निगरानी प्रभाग)REMD) द्वारा RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न डेटा स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है।
• The 10th edition introduces a new External Sector section and adds 11 new state-wise statistical tables, enhancing analysis of regional trends and disparities.
• 10वें संस्करण में एक नया बाह्य क्षेत्र)External Sector) अनुभाग जोड़ा गया है तथा 11 नए राज्यहैं गई की शामिल तालिकाएँ सांख्यिकीय वार-, जिससे क्षेत्रीय प्रवृत्तियों और असमानताओं का विश्लेषण बेहतर होता है।

Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), which digital payment system accounted for the largest share in transaction volume during FY 2024–25?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लेन के संख्या की देन-आधार पर किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही?

A) RTGS / आरटीजीएस
B) NEFT / एनईएफटी
C) IMPS / आईएमपीएस
D) UPI / यूपीआई
E) Cheques / चेक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to the RBI report, the share of small-value retail digital payments is increasing rapidly in India.
• RBI रिपोर्ट के अनुसार भारत में छोटे मूल्य के खुदरा डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ रही है।
• During FY 2024–25, digital payments recorded a growth of 17.9 percent in value terms.
• वित्त वर्ष 2024–25 में डिजिटल भुगतानों में मूल्य के आधार पर 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
• Digital payments accounted for 97.6 percent of India's total payments in value terms, highlighting their dominance in the payment ecosystem.
• मूल्य के आधार पर भारत के कुल भुगतानों में डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी 97.6 प्रतिशत रही, जो इनके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
• In volume terms, digital payments witnessed a much higher growth of 35 percent during the year.
• लेनड पर आधार के संख्या की देन-िजिटल भुगतानों में 35 प्रतिशत की तेज़ वृद्धि देखी गई।
• This surge in transaction volumes was mainly driven by the increasing use of digital modes for small-value transactions.
• यह वृद्धि मुख्य रूप से छोटे मूल्य के लेनउपय बढ़ते के माध्यमों डिजिटल में देन-ोग के कारण हुई।
• UPI emerged as the digital payment system with the largest share in transaction volume, reflecting its widespread adoption for everyday payments.

• UPI लेनउभरा बनकर माध्यम भुगतान डिजिटल बड़ा सबसे पर आधार के संख्या की देन-, जो दैनिक भुगतानों में इसके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
• In contrast, RTGS accounted for the largest share in value terms, as it is primarily used for high-value transactions.
• इसके विपरीत, मूल्य के आधार पर RTGS की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही, क्योंकि इसका उपयोग मुख्यतः उच्च मूल्य के लेनहै। जाता किया लिए के देन-
• The RBI also noted that the average value of retail digital payments declined to ₹3,830 in 2024–25 from ₹4,382 in 2023–24, indicating a rise in smaller-ticket digital transactions.
• RBI ने यह भी बताया कि खुदरा डिजिटल भुगतानों का औसत मूल्य 2023–24 के ₹4,382 से घटकर 2024–25 में ₹3,830 हो गया, जो छोटे मूल्य के डिजिटल लेन को वृद्धि में देन- है। दर्शाता

Ques: The nationwide campaign "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" (Your Money, Your Right) was concluded by which department?
"आपकी पूँजी, आपका अधिकार" अभियान का समापन किस विभाग द्वारा किया गया?

A) Department of Economic Affairs (DEA) / आर्थिक कार्य विभाग
B) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवाएँ विभाग
C) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
D) Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
E) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Department of Financial Services (DFS) concluded the nationwide campaign "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" on January 1, 2026.
• वित्तीय सेवाएँ विभाग)DFS) ने "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" राष्ट्रीय अभियान का समापन 1 जनवरी 2026 को किया।
• The campaign was launched on October 4, 2025, at Gandhinagar, Gujarat, and concluded on December 31, 2025, spanning three months.
• यह अभियान 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2025

को समाप्त हुआ, जिसकी अवधि तीन महीने रही।
• The strategy was built on three pillars: Awareness, Access, and Action, guided by the principle of Antyodaya.
• यह रणनीति तीन स्तंभों—जागरूकता, पहुँच और कार्रवाई—पर आधारित थी, जिसे अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित किया गया।
• The campaign was conducted in phases across 748 districts and helped return around ₹4,200 crore of unclaimed assets to rightful owners or their heirs.
• यह अभियान देश के 748 जिलों में चरणबद्ध रूप से चलाया गया, जिससे लगभग ₹4,200 करोड़ की लावारिस संपत्ति वास्तविक हकदारों या उनके उत्तराधिकारियों को लौटाई गई।
• At the start of the campaign, it was estimated that the Indian financial system held over ₹1.84 lakh crore in unclaimed assets (including bank deposits, insurance, and dividends).
• अभियान की शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में ₹1.84 लाख करोड़ से अधिक की लावारिस संपत्ति (बैंक जमा, बीमा और लाभांश सहित) मौजूद थी।
• Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF): Insurance proceeds unclaimed for over 10 years are transferred here, though they remain claimable by beneficiaries for up to 25 years.
• वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF): 10 वर्षों से अधिक समय से लावारिस बीमा राशि यहाँ स्थानांतरित की जाती है, हालाँकि लाभार्थी 25 वर्षों तक इस पर दावा कर सकते हैं।
• Unclaimed bank deposits (inactive for 10 years) are transferred to the Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) maintained by the RBI.
• 10 वर्षों से निष्क्रिय लावारिस बैंक जमा राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (DEA फंड) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

Ques: Which institution, in partnership with IDFC First Bank, launched a new cohort under the IGNITE programme to support technology startups?
IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में IGNITE कार्यक्रम के तहत नए स्टार्ट (कोहोर्ट) समूह अप-की ने संस्था किस शुरुआत की?

A) Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), IIT Delhi / फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर)FITT), आईआईटी दिल्ली
B) Indian Institute of Science (IISc) Bengaluru / भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
C) NITI Aayog / नीति आयोग
D) Atal Innovation Mission / अटल इनोवेशन मिशन
E) Startup India / स्टार्टअप इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), the technology transfer and incubation arm of IIT Delhi, launched a new cohort of 15 startups under the Innovation Growth & Nurturing Initiative for Technology Entrepreneurs (IGNITE) programme.
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)IIT) दिल्ली की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इनक्यूबेशन इकाई FITT ने IGNITE कार्यक्रम के तहत 15 स्टार्टकी। शुरुआत की कोहोर्ट नए के अप्स-
• The programme has been launched in partnership with IDFC First Bank.
• यह कार्यक्रम IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
• IGNITE is being implemented as part of IDFC First Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, in collaboration with FITT.
• IGNITE कार्यक्रम को IDFC फर्स्ट बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)CSR) पहल के अंतर्गत FITT के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
• Under the programme, each selected startup receives non-dilutive funding of up to ₹30 lakh.
• इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक स्टार्ट को अप-₹30 लाख तक की नॉन डायल्यूटिव-ह जाती की प्रदान फंडिंगै।
• Mentorship is provided by IIT faculty, industry experts, and CSR leaders from IDFC First Bank.
• IIT के संकाय सदस्यों, उद्योग विशेषज्ञों और IDFC फर्स्ट बैंक के CSR लीडर्स द्वारा मेंटरशिप प्रदान की जाती है।

Ques: Which two institutions signed a Memorandum of Understanding to implement a nationwide Contact Point Verification system for Informal Micro Enterprises (IMEs)?
कौन) उद्यमों सूक्ष्म अनौपचारिक ने संस्थाओं दो सी-IMEs) के लिए देशव्यापी कॉन्टैक्ट प्वाइंट वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

A) Department of Posts and RBI / डाक विभाग और RBI
B) Department of Posts and SIDBI / डाक विभाग और SIDBI
C) SIDBI and NABARD / SIDBI और NABARD

D) Ministry of MSME and SIDBI / MSME मंत्रालय और SIDBI
E) India Post Payments Bank and SIDBI / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और SIDBI

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Department of Posts and the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) signed a landmark MoU to implement a nationwide Contact Point Verification system.
• डाक विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)SIDBI) ने देशव्यापी कॉन्टैक्ट प्वाइंट वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• The initiative targets Informal Micro Enterprises registered on the Udyam Assist Platform (UAP).
• यह पहल उद्योगम असिस्ट प्लेटफॉर्म)UAP) पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित करती है।
• The objective is to provide banks and NBFCs with reliable and verified data, enabling them to extend credit under Priority Sector Lending with greater confidence.
• इसका उद्देश्य बैंकों और NBFCs को विश्वसनीय एवं सत्यापित डेटा उपलब्ध कराना है, जिससे वे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आसानी से ऋण प्रदान कर सकें।
• The app captures geo-tagged photographs of business premises to prevent ghost or fraudulent registrations.
• ऐप व्यवसाय स्थल की जियोहै लेता तस्वीरें टैग्ड-, जिससे फर्जी या "घोस्ट" पंजीकरण रोके जा सकें।
• After successful verification, IMEs receive a Udyam Assist Certificate, which is treated at par with regular Udyam Registration for banking purposes.
• सफल सत्यापन के बाद IMEs को उद्योगम असिस्ट प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, जिसे बैंकिंग उद्देश्यों के लिए सामान्य उद्योगम पंजीकरण के समकक्ष माना जाता है।

About SIDBI :

- Established : 1990
- HQ : Lucknow, Uttar Pradesh
- Chairman & MD : Manoj Mittal

Ques: Which country has introduced a new national currency with redesigned banknotes removing portraits of former leaders and undergoing redenomination?

किस देश ने पूर्व नेताओं के चित्र हटाकर और पुनर्मूल्यांकन राष्ट्रीय नई साथ के (रेडिनोमिनेशन) शुरू मुद्राकी है?

A) Lebanon / लेबनान
B) Iraq / इराक
C) Syria / सीरिया
D) Jordan / जॉर्डन
E) Egypt / मिस्र

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Syria has introduced a new national currency with redesigned banknotes.
• सीरिया ने नई डिज़ाइन वाली राष्ट्रीय मुद्रा की शुरुआत की है।
• The new banknotes have completely removed the portraits of ousted leader Bashar al-Assad and his father Hafez al-Assad, which earlier appeared on the 2,000 and 1,000 pound notes.
• नए बैंकनोटों से अपदस्थ नेता बशर अलपि उनके और असद-ता हाफ़िज़ अल चित्र के असद- हैं गए दिए हटा, जो पहले क्रमशः 2000 और 1000 पाउंड के नोटों पर थे।
• The redesigned currency now features agricultural and cultural symbols such as roses, wheat, olives, oranges, and mulberries, reflecting Syria's historical heritage.
• नई मुद्रा में गुलाब, गेहूं, जैतून, संतरे और शहतूत जैसे कृषि एवं सांस्कृतिक प्रतीक दर्शाए गए हैं, जो सीरिया की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं।
• The currency has undergone redenomination by removing two zeros to simplify daily transactions.
• दैनिक लेनदेन को सरल बनाने के लिए मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जिसमें दो शून्य हटाए गए हैं।
• Under the new system, 100 old Syrian pounds are equal to 1 new Syrian pound.
• नई व्यवस्था के अनुसार 100 पुराने सीरियाई पाउंड =1 नया सीरियाई पाउंड है।
• New denominations include 10, 25, 50, 100, 200, and 500 Syrian pounds.
• नई मुद्रा के मूल्यवर्ग 10, 25, 50, 100, 200 और 500 सीरियाई पाउंड हैं।

• The exchange period began on January 1, 2026, and will continue for 90 days, during which both old and new banknotes will circulate simultaneously.
• विनिमय अवधि 1 जनवरी 2026 से शुरू हुई है और 90 दिनों तक चलेगी, इस दौरान पुराने और नए दोनों नोट साथरहेंगे। में प्रचलन साथ-

---

Ques: Under the RBI's Scale-Based Regulation (SBR) framework for NBFCs, which layer accounts for the largest share of total NBFC assets?
आरबीआई के स्केल) रेगुलेशन बेस्ड-SBR) ढांचे के तहत एनबीएफसी की कुल परिसंपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा किस लेयर का है?

A) Base Layer (NBFC-BL) / बेस लेयर (बीएल-एनबीएफसी)
B) Middle Layer (NBFC-ML) / मिडिल लेयर (एमएल-एनबीएफसी)
C) Upper Layer (NBFC-UL) / अपर लेयर (यूएल-एनबीएफसी)
D) Top Layer / टॉप लेयर
E) All layers have equal share / सभी लेयरों का समान हिस्सा है

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Scale-Based Regulation (SBR) framework for NBFCs was introduced by the RBI in 2022 and classifies NBFCs into layers based on size, risk profile, and systemic importance.
• स्केल) रेगुलेशन बेस्ड-SBR) ढांचा आरबीआई द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, जो एनबीएफसी को आकार, जोखिम प्रोफाइल और प्रणालीगत महत्व के आधार पर विभिन्न लेयरों में वर्गीकृत करता है।
• The Middle Layer (NBFC-ML) includes all deposit-taking NBFCs and non-deposit-taking NBFCs with assets of ₹1,000 crore and above.
• मिडिल लेयर)एनबीएफसी तथा एनबीएफसी वाली करने स्वीकार जमा सभी में (एमएल-₹1,000 करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्ति वाली गैरहैं। शामिल एनबीएफसी जमा-
• This layer accounts for the largest share, i.e., 64.6% of total NBFC assets.
• इस लेयर का कुल एनबीएफसी परिसंपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा है, जो 64.6% है।
• The Base Layer has a share of 5.2%, while the Upper Layer accounts for 30.2% of total NBFC assets.
• बेस लेयर का हिस्सा 5.2% है, जबकि अपर लेयर का कुल परिसंपत्तियों में 30.2% हिस्सा है।

Ques: Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) is India's first NBFC dedicated exclusively to which sector?
सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड)SMFCL) भारत का पहला एनबीएफसी किस क्षेत्र के लिए समर्पित है?

A) Road Infrastructure / सड़क अवसंरचना
B) Power & Energy / ऊर्जा एवं विद्युत
C) Maritime Sector / समुद्री क्षेत्र
D) Aviation Sector / विमानन क्षेत्र
E) Railway Infrastructure / रेलवे अवसंरचना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) has formally commenced its lending operations, marking a historic milestone.
• सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड)SMFCL) ने औपचारिक रूप से अपने ऋण परिचालन की शुरुआत की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
• It is India's first Non-Banking Financial Company (NBFC) dedicated exclusively to the maritime sector.
• यह भारत की पहली गैर) कंपनी वित्तीय बैंकिंग-NBFC) है, जो विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र को समर्पित है।
• SMFCL approved loans worth ₹4,300 crore during its 51st Board Meeting and is targeting a loan book of ₹8,000 crore by the end of the current financial year.
• SMFCL ने अपनी 51वीं बोर्ड बैठक में ₹4,300 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक ₹8,000 करोड़ के ऋण पोर्टफोलियो का लक्ष्य रखा है।
• The Board has approved an overall borrowing limit of ₹25,000 crore.
• बोर्ड ने कुल ₹25,000 करोड़ की उधारी सीमा को मंजूरी दी है।
• Major beneficiaries include a Greenfield Port Project with an allocation of ₹4,000 crore, Dredging Corporation of India (₹150 crore), and Goa Shipyard (₹110 crore) for indigenous shipbuilding.
• प्रमुख लाभार्थियों में ₹4,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)₹150 करोड़औ (र स्वदेशी जहाज निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड)₹110 करोड़ (हैं। शामिल
• SMFCL is the nodal agency for the Maritime Development Fund (MDF) with a

total corpus of ₹25,000 crore, comprising the Maritime Investment Fund (₹20,000 crore) and the Interest Incentivisation Fund (₹5,000 crore).
• SMFCL समुद्री विकास कोष)MDF) की नोडल एजेंसी है, जिसकी कुल राशि ₹25,000 करोड़ है, जिसमें मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड)₹20,000 करोड़ इंसेंटिवाइजेशन इंटरेस्ट और ( ) फंड₹5,000 करोड़हैं। शामिल (
• The corporation also plays a key role in channelising funds under the Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS), which has an outlay of ₹44,700 crore.
• यह निगम शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम)SBFAS) के तहत ₹44,700 करोड़ की सहायता राशि के वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Ques: What was the total number of UPI transactions recorded in December 2025, marking an all-time high?
दिसंबर 2025 में UPI पर दर्ज किए गए कुल लेनदेन की संख्या कितनी थी, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है?

A) 18.45 billion
B) 19.80 billion
C) 20.12 billion
D) 21.63 billion
E) 22.90 billion

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's home-grown Unified Payments Interface (UPI) recorded an all-time high transaction volume of 21.63 billion transactions in December 2025.
• भारत के स्वदेशी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)UPI) ने दिसंबर 2025 में 21.63 बिलियन लेनदेन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया।
• The total transaction value during the month stood at ₹27.97 lakh crore.
• इस महीने के दौरान कुल लेनदेन मूल्य ₹27.97 लाख करोड़ रहा।
• Transaction volumes grew by 29 per cent year-on-year, while transaction value increased by 20 per cent.
• लेनदेन की संख्या में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ा।

• On average, UPI handled about 698 million transactions per day with a daily transaction value of ₹90,217 crore.
• औसतन, UPI ने प्रतिदिन लगभग 698 मिलियन लेनदेन संभाले, जिनका दैनिक मूल्य ₹90,217 करोड़ रहा।
• In the calendar year 2025, UPI recorded around 228 billion transactions worth nearly ₹300 lakh crore, compared to 172 billion transactions worth ₹246.82 lakh crore in 2024.
• कैलेंडर वर्ष 2025 में UPI पर लगभग 228 बिलियन लेनदेन दर्ज किए गए, जिनका मूल्य करीब ₹300 लाख करोड़ था, जबकि 2024 में 172 बिलियन लेनदेन ₹246.82 लाख करोड़ के थे।

Ques : As per RBI stress tests, what is the expected GNPA ratio of NBFCs under the baseline scenario by September 2026?
आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार, सितंबर 2026 तक आधारभूत परिदृश्य में NBFC का GNPA अनुपात कितना होने का अनुमान है?

A) 2.3%
B) 2.5%
C) 2.7%
D) 2.9%
E) 3.5%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

• Under the baseline scenario, RBI's stress tests project that the system-level Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio of NBFCs will rise from 2.3% in September 2024 to 2.9% by September 2026.
• आधारभूत परिदृश्य के तहत, आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार NBFC का सकल गैर-) परिसंपत्ति निष्पादितGNPA) अनुपात सितंबर 2024 के 2.3% से बढ़कर सितंबर 2026 तक 2.9% होने का अनुमान है।
• This indicates a gradual deterioration in asset quality, although overall capital adequacy (CRAR) is expected to remain well above the regulatory minimum of 15%.
• यह परिसंपत्ति गुणवत्ता में धीरेहै दर्शाता को गिरावट धीरे-, हालांकि समग्र पूंजी पर्याप्तता

)CRAR) नियामकीय न्यूनतम 15% से काफी ऊपर बनी रहने का अनुमान है।
• RBI also highlighted uneven resilience within the NBFC sector, with 8 NBFCs potentially falling below the minimum CRAR threshold even under the baseline scenario.
• आरबीआई ने NBFC क्षेत्र में असमान लचीलापन की ओर संकेत किया, जिसमें आधारभूत परिदृश्य में ही 8 NBFCs का CRAR न्यूनतम सीमा से नीचे जाने की संभावना है।

Ques: What key change has the Ministry of Corporate Affairs introduced regarding KYC compliance for company directors under the Companies Act, 2013?
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी निदेशकों के लिए KYC अनुपालन को लेकर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कौनहै किया बदलाव प्रमुख सा-?

A) Mandatory monthly KYC filing / अनिवार्य मासिक KYC फाइलिंग
B) Replacement of annual KYC with once-in-five-years filing / वार्षिक KYC को पाँच वर्ष में एक बार की फाइलिंग से बदलना
C) Replacement of annual KYC with once-in-three-years simplified KYC / वार्षिक KYC को तीन वर्ष में एक बार सरल KYC से बदलना
D) Complete removal of KYC requirement for directors / निदेशकों के लिए KYC आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करना
E) KYC filing applicable only to newly appointed directors / केवल नए नियुक्त निदेशकों पर KYC फाइलिंग लागू करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Corporate Affairs has eased compliance norms for company directors by replacing the mandatory annual KYC filing with a simplified KYC requirement once every three years.
• कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी निदेशकों के लिए अनिवार्य वार्षिक KYC फाइलिंग को हटाकर तीन वर्ष में एक बार सरल KYC की व्यवस्था लागू की है।
• This change follows a review of Rule 12A of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, based on the recommendations of the High-Level Committee on Non-Financial Regulatory Reforms and stakeholder

suggestions.
• यह बदलाव कंपनियाँ नियम (अर्हता एवं नियुक्ति की निदेशकों), 2014 के नियम 12A की समीक्षा के बाद किया गया है, जो गैर की समिति उच्चस्तरीय पर सुधारों विनियामक वित्तीय- है। आधारित पर सुझावों के हितधारकों और सिफारिशों
• The amended rules were notified on December 31, 2025, and will come into effect from March 31, 2026.
• संशोधित नियमों को 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया और ये 31 मार्च 2026 से प्रभावी होंगे।
• Under the revised framework, directors must submit a simplified KYC intimation once every three years instead of filing KYC annually.
• संशोधित ढांचे के तहत, निदेशकों को अब हर वर्ष के बजाय तीन वर्ष में एक बार सरल KYC सूचना देनी होगी।
• The revised KYC Form can be used for KYC compliance, updating mobile number, email address, residential address, and re-activation of Director Identification Number (DIN).
• संशोधित KYC फॉर्म का उपयोग KYC अनुपालन, मोबाइल नंबर, ईपता मेल-, आवासीय पता अद्यतन करने तथा DIN के पुनः सक्रियण के लिए किया जा सकता है।
• Digital signature verification by the director and certification by a professional will be mandatory only when the KYC form is submitted for updating mobile number, email address, or residential address.
• डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन और किसी पेशेवर द्वारा प्रमाणन केवल तभी अनिवार्य होगा, जब KYC फॉर्म मोबाइल नंबर, ई दाखिल लिए के अद्यतन के पते आवासीय या मेल- जाए। किया
• Directors who have already completed their KYC requirements are covered under the new provisions, and their next KYC filing will be due by June 30, 2028.
• जिन निदेशकों ने अब तक अपना KYC पूरा कर लिया है, वे नए प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे और उनकी अगली KYC फाइलिंग 30 जून 2028 तक देय होगी।
• Directors who have not yet submitted their KYC Form can continue to get their DIN re-activated under existing provisions till March 31, 2026.
• जिन निदेशकों ने अब तक KYC फॉर्म जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च 2026 तक मौजूदा प्रावधानों के तहत अपना DIN पुनः सक्रिय करा सकते हैं।

Ques : What percentage of the FY26 Budget Estimate did India's fiscal deficit reach during April–November 2025?
अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा FY26 बजट अनुमान का कितना

प्रतिशत रहा?

A) 52.5%
B) 58.4%
C) 60.1%
D) 62.3%
E) 65.0%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to data released by the Controller General of Accounts (CGA), India's fiscal deficit during April–November FY26 stood at **₹9.77 trillion**, which is **62.3% of the Budget Estimate (BE)** for the full financial year 2025–26.
• कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) CGA) के अनुसार, अप्रैल–नवंबर FY26 में भारत का राजकोषीय घाटा **₹9.77 ट्रिलियन** रहा, जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान का **62.3%** है।
• In the same period last year, the fiscal deficit was **₹8.5 trillion (52.5% of BE)**, indicating a higher pace of spending in the current fiscal.
• पिछले वर्ष इसी अवधि में राजकोषीय घाटा **₹8.5 ट्रिलियन)BE का 52.5%)** था, जिससे चालू वित्त वर्ष में व्यय की तेज़ गति स्पष्ट होती है।
• The rise in the deficit was mainly driven by a **28% year-on-year increase in capital expenditure**, even as **non-tax revenues remained strong**, supported by higher dividends from PSUs, public sector banks, and the RBI.
• घाटे में वृद्धि का प्रमुख कारण **पूंजीगत व्यय में 28% की वार्षिक वृद्धि** रही, हालांकि **PSU, सरकारी बैंकों और RBI से अधिक लाभांश** मिलने से गैर मजबूत राजस्व कर-बना रहा।
• The Centre has targeted a **fiscal deficit of 4.4% of GDP for FY26**.
• केंद्र सरकार ने FY26 के लिए **GDP के 4.4%** का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा है।

Ques: Which group has received in-principle approval from SEBI to act as sponsor and establish a new Mutual Fund?
किस समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और नया म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है?

A) Motilal Oswal Group / मोतीलाल ओसवाल समूह
B) Edelweiss Group / एडलवाइस समूह

C) Ashika Group / आशिका समूह
D) JM Financial Group / जेएम फाइनेंशियल समूह
E) IIFL Group / आईआईएफएल समूह

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Ashika Group has received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to act as a sponsor and establish Ashika Mutual Fund.
• आशिका समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और आशिका म्यूचुअल फंड की स्थापना के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) सेबी (से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है।
• This approval allows the group to form an Asset Management Company (AMC) and initiate preparations for launching mutual fund schemes, subject to final registration.
• इस मंजूरी के तहत समूह को एसेट मैनेजमेंट कंपनी) AMC) गठित करने और अंतिम पंजीकरण के अधीन म्यूचुअल फंड योजनाओं की तैयारी करने की अनुमति मिली है।
• Ashika Group was established in 1994 and operates as a comprehensive financial services platform.
• आशिका समूह की स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक वित्तीय सेवा मंच के रूप में कार्य करता है।

Ques: Who has been given additional charge as the interim Managing Director & CEO of Canara Bank?
केनरा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है?

A) Satyanarayana Raju | सत्यनारायण राजू
B) Brajesh Kumar Singh | ब्रजेश कुमार सिंह
C) Hardeep Singh Ahluwalia | हरदीप सिंह अहलूवालिया
D) Rajnish Kumar | रजनीश कुमार
E) Ashok Chandra | अशोक चंद्र

Answer : Option C

Explanation | व्याख्या:

• Canara Bank has assigned the additional charge of Managing Director & CEO to its Executive Director, Hardeep Singh Ahluwalia, with effect from January 1, 2026.

• केनरा बैंक ने 1 जनवरी 2026 से अपने कार्यकारी निदेशक हरदीप सिंह अहलूवालिया को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

• The interim appointment will remain valid for three months, or until a regular MD & CEO is appointed, or until further orders.

• यह अंतरिम नियुक्ति तीन महीनों के लिए या नियमित एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी।

• The decision follows the superannuation of the incumbent MD & CEO, Satyanarayana Raju.

• यह निर्णय वर्तमान एमडी एवं सीईओ सत्यनारायण राजू के सेवानिवृत्त होने के बाद लिया गया है।

• Hardeep Singh Ahluwalia joined the banking sector in 1992 as an Agricultural Field Officer at Allahabad Bank (now Indian Bank) and has over three decades of experience across diverse banking segments.

• हरदीप सिंह अहलूवालिया ने 1992 में इलाहाबाद बैंक) अब इंडियन बैंक (में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में बैंकिंग करियर शुरू किया था और उन्हें विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।

• The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) has recommended Brajesh Kumar Singh, currently Executive Director at Indian Bank, as the next regular MD & CEO of Canara Bank.

• वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो) FSIB) ने वर्तमान में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक ब्रजेश कुमार सिंह को केनरा बैंक के अगले नियमित एमडी एवं सीईओ के रूप में सिफारिश की है।

Ques: What decision did the Department of Economic Affairs (DEA) take regarding Small Savings Schemes (SSS) interest rates for January–March 2026?

जनवरी–मार्च 2026 के लिए लघु बचत योजनाओं)SSS) की ब्याज दरों को लेकर आर्थिक कार्य विभाग)DEA) ने क्या निर्णय लिया?

A) Interest rates were increased / ब्याज दरें बढ़ाई गईं
B) Interest rates were reduced / ब्याज दरें घटाई गईं
C) Interest rates were kept unchanged / ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गईं
D) Only select schemes saw a hike / केवल कुछ योजनाओं में वृद्धि हुई
E) Quarterly revision system was discontinued / तिमाही संशोधन प्रणाली समाप्त की गई

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance kept interest rates unchanged for all Small Savings Schemes from January 01, 2026 to March 31, 2026, continuing the rates of Q3FY26.
• वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग ने 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को Q3FY26 के समान अपरिवर्तित रखा।
• This is the 8th consecutive quarter with no change in SSS interest rates.
• यह लगातार आठवीं तिमाही है जब SSS की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
• The interest rates were last revised in Q4FY24.
• SSS की ब्याज दरों में अंतिम संशोधन Q4FY24 में किया गया था।
• Small Savings Schemes are Government of India–backed instruments that promote household savings and provide risk-free investment options.
• लघु बचत योजनाएं भारत सरकार समर्थित साधन हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू बचत को बढ़ावा देना और जोखिमहै। देना विकल्प निवेश मुक्त-
• Since 2016, SSS interest rates have been notified quarterly by the DEA based on bond yields and market trends.
• 2016 से SSS की ब्याज दरें बॉन्ड यील्ड और बाजार रुझानों के आधार पर तिमाही रूप से DEA द्वारा अधिसूचित की जाती हैं।
• The methodology for determining SSS interest rates was recommended by the श्यामला गोपीनाथ समिति in January 2023.
• SSS की ब्याज दर तय करने की पद्धति जनवरी 2023 में श्यामला गोपीनाथ समिति द्वारा सुझाई गई थी।
• The committee recommended rates should be 25 to 100 basis points higher than government bond yields.
• समिति ने सुझाव दिया कि इन योजनाओं की ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड यील्ड से 25 से 100 बेसिस प्वाइंट अधिक होनी चाहिए।

Interest Rates on Small Savings Schemes for Q4FY26 (1st January, 2026 to 31st March, 2026):

- Post Office Savings Deposit : 4.0%
- 1-Year Post Office Time Deposits : 6.9%
- 2-Year Post Office Time Deposits : 7.0%
- 3-Year Post Office Time Deposits : 7.1%
- 5-Year Post Office Time Deposits : 7.5%
- 5-Year Post Office Recurring Deposits : 6.7%
- Kisan Vikas Patra : 7.5% (will mature in 115 months)
- Public Provident Fund : 7.1%
- Sukanya Samriddhi Yojana : 8.2%
- National Savings Certificate : 7.7%
- Senior Citizen Savings Scheme : 8.2%
- Post Office Monthly Income Scheme : 7.4%
- Mahila Samman Savings Certificate : 7.5%

Ques: What is the title of the podcast series launched by the Reserve Bank of India to enhance public communication?
सार्वजनिक संचार को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नाम क्या है?

A) RBI Speaks: Economy Explained / RBI स्पीक्सएक्सप्लेंड इकोनॉमी :
B) Paisa aur Arthvyavastha / पैसा और अर्थव्यवस्था
C) RBI Talks: Paisa to Policy / RBI टॉक्सपॉलिसी टू पैसा :
D) Monetary Matters by RBI / RBI द्वारा मॉनेटरी मैटर्स
E) Policy to Public / पॉलिसी टू पब्लिक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India proposed adding podcasts to its communication toolkit to widely disseminate information of public interest.
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने के लिए पॉडकास्ट को

अपने संचार साधनों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
• Accordingly, RBI launched its podcast series titled “RBI Talks: Paisa to Policy.”
• इसके तहत RBI ने “RBI Talks: Paisa to Policy” नामक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की।
• The first episode of the series is titled “Demystifying KYC.”
• इस श्रृंखला का पहला एपिसोड “Demystifying KYC” शीर्षक से जारी किया गया है।

Ques: What is the key objective of RBI’s NBFC (Prudential Norms on Capital Adequacy) Amendment Directions, 2026?
RBI द्वारा जारी NBFC (पूंजी पर्याप्तता विवेकपूर्ण मानदंडनिर्देश संशोधन (, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) Increasing capital requirements for all NBFC loans / सभी NBFC ऋणों के लिए पूंजी आवश्यकता बढ़ाना
B) Providing subsidies for infrastructure projects / अवसंरचना परियोजनाओं को सब्सिडी देना
C) Easing capital adequacy norms for NBFC lending to high-quality infrastructure projects / उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने वाले NBFC के लिए पूंजी मानदंडों में ढील देना
D) Restricting NBFC exposure to infrastructure sector / NBFC के अवसंरचना क्षेत्र में जोखिम को सीमित करना
E) Introducing new licensing norms for NBFCs / NBFC के लिए नए लाइसेंसिंग नियम लागू करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The RBI has eased capital adequacy norms for Non-Banking Finance Companies (NBFCs) lending to high-quality infrastructure projects through Amendment Directions, 2026.
• RBI ने उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने वाले NBFC के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है।
• Risk weight has been reduced to 75% if at least 2% of sanctioned project debt is repaid, instead of the earlier draft requirement of 5% but less than 10%.
• यदि स्वीकृत परियोजना ऋण का कम से कम 2% चुका दिया गया है, तो जोखिम भार 75%

होगा।
• A lower 50% risk weight will apply if at least 5% of the sanctioned project debt is repaid, relaxed from the earlier 10% threshold.
• यदि कम से कम 5% ऋण चुका दिया गया है, तो जोखिम भार 50% होगा।
• The directions will be applicable from April 1, 2026, or earlier if adopted fully by an NBFC.
• ये निर्देश 1 अप्रैल 2026 से या NBFC द्वारा पहले अपनाने पर लागू होंगे।
• A project will be considered high-quality if it has completed one year after Commercial Operation Date (COD), has no material covenant breach, and is classified as standard.
• परियोजना को उच्च गुणवत्ता वाली माना जाएगा यदि COD के बाद एक वर्ष पूरा हो चुका हो और वह स्टैंडर्ड श्रेणी में हो।
• NBFCs may continue existing risk weights until the next review or March 31, 2027, whichever is earlier.
• NBFC अगले पुनरीक्षण या 31 मार्च 2027 तक मौजूदा जोखिम भार जारी रख सकते हैं।

Ques: What percentage of ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 has been returned so far?
19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद ₹2000 के नोटों में से अब तक कितना प्रतिशत वापस आ चुका है?

A) 95.20%
B) 96.85%
C) 97.40%
D) 98.41%
E) 99.10%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The total value of ₹2000 banknotes in circulation was ₹3.56 lakh crore on May 19, 2023, when their withdrawal was announced.
• 19 मई 2023 को ₹2000 के नोटों की कुल प्रचलित राशि ₹3.56 लाख करोड़ थी।
• This value declined sharply to ₹5,669 crore by the close of business on December 31, 2025.

• 31 दिसंबर 2025 तक यह घटकर ₹5,669 करोड़ रह गई।
• As a result, 98.41% of the ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 have been returned.
• इस प्रकार 19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद ₹2000 के 98.41% नोट वापस आ चुके हैं।
• The facility for deposit and/or exchange was available at all bank branches till October 7, 2023.
• जमा या विनिमय की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।
• Exchange of ₹2000 banknotes continues at 19 RBI Issue Offices since May 19, 2023.
• ₹2000 के नोटों के विनिमय की सुविधा 19 RBI इश्यू कार्यालयों में 19 मई 2023 से उपलब्ध है।

Ques: What is the interest rate on the RBI Floating Rate Savings Bond, 2020 (Taxable) for the period January–June 2026?
जनवरी–जून 2026 की अवधि के लिए RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, 2020 (करयोग्य की (है क्या दर ब्याज?

A) 7.70%
B) 7.85%
C) 8.00%
D) 8.05%
E) 8.35%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The interest rate on the Floating Rate Savings Bond, 2020 (Taxable) has been announced for the period January 1, 2026 to June 30, 2026.
• फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, 2020 (करयोग्य दर ब्याज की (1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए घोषित की गई है।
• The bond carries a floating interest rate, which is reset every six months, and has a maturity period of seven years.
• इस बॉन्ड की ब्याज दर परिवर्तनीय है, जिसे हर छह महीने में रीसेट किया जाता है, और इसकी परिपक्वता अवधि सात वर्ष है।
• Interest on the bond is paid twice a year, on January 1 and July 1.

• इस बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
• The coupon rate is fixed at 35 basis points (0.35%) above the National Savings Certificate (NSC) rate.
• कूपन दर राष्ट्रीय बचत पत्र)NSC) की ब्याज दर से 35 बेसिस पॉइंट)0.35%) अधिक निर्धारित की जाती है।
• For the current half-year, the NSC rate is 7.70%, making the FRSB interest rate 8.05%.
• वर्तमान अर्धवार्षिक अवधि के लिए NSC की दर 7.70% है, जिससे FRSB की ब्याज दर 8.05% बनती है।
• Interest for this period will be paid on July 1, 2026, and since the bond is taxable, the interest is added to income and taxed as per applicable slabs.
• इस अवधि का ब्याज 1 जुलाई 2026 को दिया जाएगा और यह करयोग्य होगा, जिसे आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा।

Ques: Asian Development Bank (ADB) provided ₹4,100 crore assistance to which state for Musi Riverfront Development Project Phase-I?
एशियाई विकास बैंक)ADB) ने मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना चरण-I के लिए किस राज्य को ₹4,100 करोड़ की सहायता दी?

A) Telangana / तेलंगाना
B) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
C) Tamil Nadu / तमिलनाडु
D) Karnataka / कर्नाटक
E) Maharashtra / महाराष्ट्र

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Asian Development Bank provided ₹4,100 crore (USD 500 million) to the Government of Telangana.
• एशियाई विकास बैंक ने तेलंगाना सरकार को ₹4,100 करोड़)500 मिलियन अमेरिकी डॉलरकिए। प्रदान (
• The amount was given to the Minister for Industries and Commerce, Government of Telangana.

• यह राशि तेलंगाना सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री को दी गई।
• The assistance is for Phase-I of the Musi Riverfront Development Project.
• यह सहायता मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना के प्रथम चरण के लिए है।
• The project aims to rejuvenate and restore the Musi River.
• इस परियोजना का उद्देश्य मुसी नदी का पुनर्जीवन करना है।

Ques: Who chaired the first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB)?
पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड)PRB) की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की?

A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
B) S Krishnan / एसकृष्णन .
C) T Rabi Sankar / टीशंकर रबी .
D) Aruna Sundararajan / अरुणा सुंदरराजन
E) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB) was held in Mumbai under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra.
• पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड)PRB) की पहली बैठक मुंबई में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई।
• The Board reviewed the functioning of the Department of Payment and Settlement Systems and domestic and global payment systems.
• बोर्ड ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग तथा घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणालियों की समीक्षा की।
• The draft Payments Vision 2028 was presented for strategic guidance.
• ड्राफ्ट पेमेंट्स विजन 2028 प्रस्तुत किया गया।
• PRB was constituted after amendment to the Payment and Settlement Systems Act, 2007, effective from 9 May 2025.
• PRB का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में 9 मई 2025 से प्रभावी संशोधन के बाद किया गया।
• PRB replaced the Board for Regulation and Supervision of Payment and

Settlement Systems (BPSS).
• PRB ने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड)BPSS) का स्थान लिया।
• Members present included S Krishnan, Nagaraju Maddirala, Aruna Sundararajan, T Rabi Sankar, and Vivek Deep.
• बैठक में एसकृष्णन ., नागराजू मड्डीराला, अरुणा सुंदरराजन, टी विवेक और शंकर रबी . थे। उपस्थित दीप

Ques: Who has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank?
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) R. P. Ramakrishnan / आररामकृष्णन .पी .
B) Karthikeyan Manickam / कार्तिकेयन मणिक्कम
C) K. Paul Thomas / केथॉमस पॉल .
D) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
E) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Karthikeyan Manickam, former Executive Director (ED) of Bank of India, has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank (ESAF SFB).
• बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक)ED) कार्तिकेयन मणिक्कम को ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• He replaced R. P. Ramakrishnan in this position.
• उन्होंने इस पद पर आरहै। लिया स्थान का रामकृष्णन .पी .
• ESAF Small Finance Bank was established on 10 March 2017.
• ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 10 मार्च 2017 को हुई थी।
• The headquarters of ESAF Small Finance Bank is located in Thrissur, Kerala.
• ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय त्रिशूर, केरल में स्थित है।
• Shri K. Paul Thomas is the Managing Director and CEO of the bank.
• श्री के) निदेशक प्रबंध के बैंक थॉमस पॉल .MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)CEO) हैं।

Ques: Which bank launched the Zero-Forex Diamond Reserve Credit Card offering zero foreign exchange markup for frequent international travellers?
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शून्य विदेशी मुद्रा) फॉरेक्स (मार्कअप वाला ज़ीरो-फॉरेक्स डायमंड रिज़र्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
D) IDFC FIRST Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• IDFC FIRST Bank launched the Zero-Forex Diamond Reserve Credit Card as a premium offering for frequent international travellers.
• आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रीमियम ज़ीरो-फॉरेक्स डायमंड रिज़र्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
• The card provides zero foreign exchange (forex) markup along with travel and lifestyle rewards.
• यह कार्ड शून्य विदेशी मुद्रा) फॉरेक्स (मार्कअप के साथ यात्रा और लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स प्रदान करता है।
• The annual fee is ₹3,000 plus GST, which is waived from the second year on annual spends of ₹6 lakh.
• इसका वार्षिक शुल्क ₹3,000 प्लस जीएसटी है, जो ₹6 लाख के वार्षिक खर्च पर दूसरे वर्ष से माफ कर दिया जाता है।

Ques: What time lag has SEBI proposed for sharing and using price data in investor education and awareness programmes?
निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के साझा करने और उपयोग के लिए सेबी ने कितने समय के अंतराल) टाइम लैग (का प्रस्ताव किया है?

A) 1 day
B) 7 days

C) 15 days
D) 30 days
E) 90 days

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• SEBI has proposed a uniform 30-day time lag for sharing and using price data in investor education and awareness programmes.
• सेबी ने निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के उपयोग के लिए 30 दिनों के समान समय अंतराल का प्रस्ताव किया है।
• The proposal aims to prevent misuse of sensitive market data while ensuring educational content remains relevant and timely for investors.
• इस प्रस्ताव का उद्देश्य संवेदनशील बाजार डेटा के दुरुपयोग को रोकते हुए निवेशकों के लिए शैक्षिक सामग्री को प्रासंगिक बनाए रखना है।
• This move replaces the earlier system where exchanges shared data with a one-day lag while educators could use only data that was at least three months old.
• यह कदम पुराने तंत्र की जगह लेता है, जिसमें एक्सचेंज एक दिन की देरी से डेटा साझा करते थे जबकि शिक्षकों को कम से कम तीन महीने पुराने डेटा का उपयोग करना पड़ता था।

Ques: With which institution did the Delhi Government sign an MoU to bring its finances under a complete banking, cash management, and debt management framework for the first time?
दिल्ली सरकार ने पहली बार अपनी बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन व्यवस्था को किस संस्था के अंतर्गत लाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन)MoU) पर हस्ताक्षर किए?

A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) NITI Aayog / नीति आयोग
E) Comptroller and Auditor General / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Delhi Government signed a Memorandum of Understanding with the Reserve Bank of India to operate under RBI's complete banking, cash management, and debt management framework for the first time.
• दिल्ली सरकार ने पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत कार्य करने के लिए RBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• This move aligns Delhi's financial governance with nationally accepted fiscal practices.
• यह कदम दिल्ली की वित्तीय व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत राजकोषीय प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।
• The Reserve Bank of India traditionally acts as banker and debt manager for state governments.
• भारतीय रिज़र्व बैंक परंपरागत रूप से राज्य सरकारों के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है।
• RBI manages state governments' borrowings, cash balances, and debt instruments under frameworks approved by the Centre.
• RBI केंद्र द्वारा स्वीकृत ढांचे के तहत राज्यों की उधारी, नकद शेष और ऋण साधनों का प्रबंधन करता है।

Ques: Which bank will facilitate bilateral trade settlements between India and Israel in Indian rupees through a Special Rupee Vostro Account?
भारत और इज़राइल के बीच भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार निपटान को विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से कौन सा बैंक सुगम बनाएगा?

A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's largest lender, the State Bank of India, will facilitate bilateral trade settlements between India and Israel in Indian rupees.
• भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, भारत और इज़राइल के बीच रुपये में द्विपक्षीय व्यापार निपटान को सुगम बनाएगा।
• The move is aligned with ongoing discussions between the two countries towards a comprehensive Free Trade Agreement.
• यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में चल रही चर्चाओं से जुड़ा है।
• Under the mechanism, Israeli exporters and importers will make and receive payments in rupees through a Special Rupee Vostro Account linked to trade invoices.
• इस व्यवस्था के तहत इज़राइली निर्यातक और आयातक व्यापार चालानों से जुड़े विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपये में भुगतान करेंगे।
• SBI's Tel Aviv branch has obtained all regulatory approvals to operationalise the arrangement and is promoting awareness among stakeholders.
• एसबीआई की तेल अवीव शाखा ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी नियामक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ा रही है।

Ques: Which company became the first payments firm in India, the Middle East, APAC, and South Africa to receive the ISO/IEC 42001 certification for Artificial Intelligence Management Systems?
भारत, मध्य पूर्व, एशिया-प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO/IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी?

A) Paytm / पेटीएम
B) Razorpay / रेज़रपे
C) PhonePe / फोनपे
D) NPCI / एनपीसीआई
E) Financial Software and Systems (FSS) / फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• Financial Software and Systems (FSS) became the first payments company across India, the Middle East, APAC, and South Africa to earn the ISO/IEC 42001 certification.

• फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स) FSS) भारत, मध्य पूर्व, एशिया-प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO/IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बनी।

• ISO/IEC 42001 is the world's first international standard for Artificial Intelligence Management Systems (AIMS).

• ISO/IEC 42001 कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली) AIMS) के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है।

• The certification recognises organisations that demonstrate responsible, ethical, and trustworthy use of artificial intelligence.

• यह प्रमाणन एआई के जिम्मेदार, नैतिक और विश्वसनीय उपयोग को प्रदर्शित करने वाले संगठनों को मान्यता देता है।

EXAM Genius